



मर्चेंट डजिटिइज़ेशन सम्मेलन- 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबरस ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) और संयुक्त राष्ट्र संघ के 'बेटर दैन कैश अलायंस' (UN-based Better Than Cash Alliance) द्वारा संयुक्त रूप से 'मर्चेंट डजिटिइज़ेशन सम्मेलन 2021: आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना' (Merchant Digitization Summit 2021: Towards Atmanirbhar (Self Reliance) Bharat) की मेज़बानी की गई।

- इस सम्मेलन से सार्वजनिक और नजीक क्षेत्र के अग्रणी लोगों को साथ आने का मौका मिला है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र और आकांक्षी जिलों के कारोबारियों को जवाबदेह डजिटलीकरण (Responsible Digitization) को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करेगा।

प्रमुख बंदि:

हाईलाइट्स :

- उन महिला व्यापारियों को सशक्त बनाना जो अपने समुदायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, डजिटल इंडिया मिशन को प्राप्त करने में मदद करना इसकी प्राथमिकताओं में से एक है।
- राष्ट्रीय भाषा अनुवाद अभियान (National Language Translation Mission) के तहत इसके प्रति विश्वास बढ़ाने हेतु डजिटल भुगतान सूचनाओं के प्रसार और नजिता नियमों आदिको स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जा सकता है।
- अंतिम पायदान पर मौजूद व्यापारियों हेतु कनेक्टिविटी, स्मार्टफोन तक उनकी पहुँच और डजिटल साक्षरता की चुनौतियों को दूर करने पर भी सम्मेलन में सहमतिव्यक्त की गई।
- आत्मनिर्भर भारत योजना के माध्यम से 'भेक इन इंडिया' पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए जवाबदेह डजिटलीकरण द्वारा ग्रामीण नेटवर्क में स्व-सहायता समूह और समुदाय के स्तर पर लोगों को शामिल करना।
 - इससे लाखों व्यापारियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल करने हेतु स्थानीय स्तर पर डजिटल पारस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सकेगा ताकि वे आसानी से कर्रज लेकर अपने व्यापार का वसितार कर सकें।
- भारत ने प्रतिमाह औसतन 2-3 बलियन डजिटल लेन-देन करने के बाद अब प्रतिदिन 1 बलियन डजिटल लेने-देन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
 - इसके तहत ग्राहक और कारोबारी के बीच हर माह 10-12 अरब डजिटल लेन-देन का हस्तांतरण भारत की डजिटल अर्थव्यवस्था में योगदान देगा।

हाल की पहलें:

- डजिटल भुगतान सूचकांक।
- 'भुगतान अवसंरचना विकास कोष' योजना।
- मर्चेंट डसिकाउंट रेट में छूट।

बेटर दैन कैश अलायंस (BTCA):

- **BTCA के बारे में:** BTCA सरकारों, कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच एक साझेदारी है जिसके तहत सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु डजिटल भुगतानों को तीव्रता के साथ किया जाता है।
- **स्थापना:** इसे यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, बलि एंड मेलडिा गेट्स फाउंडेशन, सॉर्टि ग्रुप, फोर्ड फाउंडेशन, ओमडियार नेटवर्क तथा वीज़ा इंक द्वारा लॉन्च किया गया था।
 - इसकी मेज़बानी संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (UNCDF) के न्यूयॉर्क, बोगोटा, डकार, ढाका, कगाली, लंदन, मनीला और नई दिल्ली कार्यालयों द्वारा की जाती है।
 - इसका गठन वर्ष 2012 में किया गया था।
- **सदस्य:** इस एलायंस में 75 सदस्य हैं जो दक्षता, पारदर्शिता, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भुगतानों को डजिटल बनाने हेतु प्रतिबद्ध हैं तथा उन अर्थव्यवस्थाओं के निर्माण में मदद करते हैं जो डजिटल और समावेशी हैं।

- इसके सदस्य नकदी के भौतिक लेन-देन को समाप्त नहीं करना चाहते हैं, बल्कि एक ज़िम्मेदार डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करना चाहते हैं जो "नकदी से बेहतर" है।
- वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान को डिजिटिज़ करने तथा विश्व के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, [प्रधानमंत्री जन धन योजना](#) की सफलता की कहानियों को साझा करने के उद्देश्य से भारत वर्ष 2015 में बेटर दैन कैश अलायंस का सदस्य बन गया।

भारतीय वाणज्य और उद्योग महासंघ (फकिकी)

- फकिकी एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी।
- यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना शीर्ष व्यापारिक संगठन है जिसका इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम से निकटता से जुड़ा है, इसका औद्योगीकरण तथा उद्भव सर्वाधिक तीव्र गति से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/merchant-digitization-summit-2021>

